दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार, 04 मार्च 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 156

महत्वपूर्ण एवं खास

देश में एक दिन में कोरोना के 6561 नये मरीज, 142 की मौत

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 6561 नये मामले सामने आये। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 77,152 रह गयी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में 142 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढक़र 5,14,388 हो गयी। पिछले 24 घंटे के दौरान उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 8,528 की कमी दर्ज की गयी। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढक़र 98.62 प्रतिशत हो गयी है। संक्रमण की दैनिक दर 0.74 और साप्ताहिक दर 0.99 प्रतिशत दर्ज की गयी। देश में कोरोना के कुल 4,29,45,160 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,23,53,620 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना से मृत्यु दर 1.20 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोरोना रोधी टीकों की 178.02 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।

कंटेनर ने आटो को मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत

सागर (आरएनएस)। झांसी-लखनादौन नेशनल हाईवे 44 पर कैंट थाना क्षेत्र के रानीपुरा गांव के पास गत मंगलवा-बुधवार दरम्यानी रात करीब एक बजे कंटेनर एसयूपी को टक्कर मारने के बाद आटो से जा भिड़ा, हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। आटो सवार बम्होरी गांव में विवाह समारोह से अपने गांव सिंगना लौट रहे थे। मृतकों की पहचान बैंडबाजा पार्टी के बलचंद धानक, लखन धानक व धुरु धानक के रूप में हुई है।

डम्फर की चपेट में आने से माँ-बेटे की मौत

भिलाई (आरएनएस)। डंपर की टक्कर से मां-बेटे की मौत हो गई। दोनों स्कूटी से ट्रांसपोर्ट नगर जा रहे थे। तभी सामने से आए डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक डंपर छोडक़र भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसा खुर्सीपार थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक, पुरैना के डाकबंगला निवासी शशिकला मिश्रा अपने बेटे अश्वनी मिश्रा (30) को उसके काम पर छोडऩे के लिए सुबह करीब 8 बजे स्कूटी से ट्रांसपोर्ट नगर जा रही थीं। अभी वे डबरापारा तिराहे पर पहुंचे थे कि सामने से आ रहे डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्कूटी डंपर में फंसकर घिसटती चली गई। हादसा होते देख लोगों ने शोर मचाया तो चालक डंपर छोडक़र भाग निकला।

कार और ट्रक में भीषण टक्कर, पांच लोगों की मौत

गुरुग्राम (आरएनएस)। गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर बुधवार देर रात बिनौला गांव के पास एक कार के ट्रक से टकरा जाने के कारण पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, बुधवार देर रात करीब दो बजे एक तेज रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बरामद करने में कामयाब रही। दुर्घटनाग्रस्त कार राजस्थान में पंजीकृत है और उस पर राजस्थान की नंबर प्लेट है।

महाराष्ट्र के मंत्री मलिक की ईडी हिरासत 7 तक बढ़ी

मनी लॉन्ड्रिंग केस

मुंबई (आरएनएस)। यहां की एक विशेष अदालत ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत बृहस्पतिवार को 7 मार्च तक बढ़ा दी। मलिक को दक्षिण मुंबई स्थित ईडी के कार्यालय में लगभग 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गत 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। शुरुआती हिरासत अवधि खत्म होने के बाद बृहस्पतिवार को उन्हें न्यायाधीश आरएन रोकाडे की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने मामले में आगे की जांच के लिये उनकी हिरासत 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। अदालत ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी 25 से 28 फरवरी (अपनी पिछली ईडी हिरासत के दौरान) अस्पताल में था और जांच के दौरान नए तथ्य भी सामने आए हैं, आरोपी को हिरासत में भेजा जा रहा है। ईडी का मामला दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ हाल ही में एनआईए द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

18000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ा, 6400 वापस घर आए, खारकीव में अभी भी फंसे है भारतीय

नई दिल्ली (आरएनएस)। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से करीब 18 हजार भारतीय युद्धग्रस्त देश को छोड़ चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारी पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद से कुल 18,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन की सीमा छोड़ चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानें अब तक यूक्रेन से 6,400 भारतीयों को वापस ला चुकी हैं। अगले 24 घंटों में, 18 उड़ानें निर्धारित की गई हैं।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमें यूक्रेनी अधिकारियों के सहयोग से पता चला है कि, कई छात्रों ने कल खारकीव छोड़ दिया। कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए हम यूक्रेन और रूस के संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआत में यूक्रेन में 20,000 भारतीय नागरिकों का पंजीकरण किया गया था, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया था। हमारा अनुमान है कि कुछ सौ नागरिक अभी भी खारकीव में रह रहे हैं। हमारी प्राथमिकता छात्रों को सुरक्षित रूप से बाहर ले जाना है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के अभियान की गति लगातार तेज हो रही है। इसने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 15 उड़ानें उतरीं, 3,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। यूक्रेन से निकासी प्रक्रिया पर बयान देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीयों को वापस लाने के वास्ते अगले 24 घंटों के लिए 18 उड़ान निर्धारित की गई हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि उड़ानों की यह संख्या उन बड़ी संख्या में भारतीयों को दर्शाती है जो यूक्रेन से पार कर गए हैं और अब पड़ोसी देशों में हैं। हम इन सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए लगाई गईं फ्लाइट्स में 3 फ्लाइट भारतीय वायुसेना सी-17 हैं बाकी के कमर्शिलय फ्लाइट हैं, जिनमें एयर इंडिया, ईडिको,स्पाइस जेट, गो एयर और गो फर्स्ट के फ्लाइट है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, हम और उड़ानें शेड्यूल कर रहे हैं और अगले 2-3 दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय वापस लौट आएंगे। मैं अपने लोगों की मेजबानी करने और उन्हें निकालने में सहायता प्रदान करने के लिए यूक्रेन की सरकार और पड़ोसी देशों की सराहना करना चाहता हूं।

यूक्रेन संकट : भारतीयों को निकालने लिए आईएएफ ने भेजे तीन और सी-17 विमान

रूस और यूक्रेन का जंग जारी है। इसी बीच फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए गुरुवार को भारतीय वायु सेना ने अपने तीन और सी-17 विमानों को रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के लिए भेजा है। अधिकारियों ने कहा कि सी-17 में से एक विमान की आज रात लौटने की उम्मीद है, जबकि अन्य दो के शुक्रवार सुबह उतरने की उम्मीद है। वायुसेना के भारी क्षमता वाले सी-17 विमान में करीब 200 लोग बैठ सकते हैं। यूक्रेन और रूस के जंग के बीच फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को तीन देशों के 798 यात्रियों को भी वापस लाया।

वहीं, भारत ने बुधवार को रोमानिया, पोलैंड और हंगरी में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चल रहे राष्ट्रीय प्रयास में शामिल होने के लिए चार सी -17 विमान लॉन्च किए थे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना को ऑपरेशन गंगा में शामिल होने को कहा था।

सी-17 विमान ने मुश्किल समय में अहम रोल अदा किया है। पिछले साल जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद अपने चरम पर था, तो सी-17 ने सैनिकों और सैन्य उपकरणों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, पिछले साल इन हवाई जहाजों का उपयोग कोविड के दौरान बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कंटेनरों के परिवहन के लिए भी किया गया था।

विमान का इस्तेमाल पिछले साल अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भी किया गया था। यह हाल के वर्षों में नेपाल, मालदीव और यमन में मानवीय मिशनों में भी शामिल रहा है।

वायुसेना का यह विमान भारी भरकम बेड़े को संचालित करता है, जिसे करीब 4.5 बिलियन डॉलर के सौदे में अमेरिका से खरीदा गया है। इस विमान की खासियत यह है कि यह 72,574 किलोग्राम के भार के साथ उड़ान भर सकता है और 3,000 फीट से कम माप वाले एक छोटे, बिना तैयार रनवे पर भी उतर सकता है।

चारधाम यात्रा : ग्रीन कार्ड के साथ ट्रिप कार्ड भी अनिवार्य

ऋषिकेश (आरएनएस)। चारधाम यात्रा 2022 में इस बार धामों में रवाना होने से पहले व्यावसायिक और प्राइवेट वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड के साथ ही ट्रिप कार्ड लेना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग की वेबसाइट पर 15 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीते दो साल वैश्विक महामारी कोरोना के चलते चारधाम यात्रा प्रभावित रही। इस बार संक्रमण में कमी के कारण चारधाम यात्रा की तैयारियां जोर पकडऩे लगी हैं। मई से चारधाम यात्रा शुरू होगी। यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने भी व्यवस्थाओं को अमलीजामा पहनाना आरंभ कर दिया है। चारधाम यात्रा में संचालित व्यवसायिक और निजी वाहनों के लिए इस बार ग्रीन कार्ड के साथ ट्रिप कार्ड अनिवार्य कर दिया है। ताकि चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों और तीर्थयात्रियों की संख्या का रिकार्ड रखा जा सके। कौन सा वाहन कितने फेरे लगा रहा है, इसका भी रिकॉर्ड रहेगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट संभवतया 15 अप्रैल से खोल दी जाएगी। बताया कि एआरटीओ में भी ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड ऑनलाइन जारी करने के लिए चार काउंटर खोले जाएंगे, ताकि बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को दिक्कत नहीं हो।

1 मई से खुलेंगे चेकपोस्ट- चारधाम यात्रा में वाहनों का संचालन व्यस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग ऋषिकेश में भद्रकाली तिराहा और ब्रह्मपुरी में एक मई से चेकपोस्ट खोलेगा। जहां प्रवर्तन दल की तैनाती रहेगी, जो यात्रा पर जाने वाले वाहनों के कागजात आदि की जांच करेंगे। साथ ही डग्गामार वाहनों के संचालन पर रोक लगाएंगे।

फिटनेस के लिए आना होगा एआरटीओ- यात्रा पर संचालित वाहनों के मालिक ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर कहीं से भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वाहनों की फिटनेस के लिए वाहन को लेकर एआरटीओ आना होगा। फिटनेस के बाद ही ग्रीन कार्ड मान्य होगा।

आयकर विभाग का एक प्रमुख दूरसंचार समूह में तलाशी और जब्ती अभियान

नईदिल्ली (आरएनएस)। आयकर विभाग ने 15 फरवरी को दूरसंचार उत्पादों के वितरण और कैप्टिव सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एक बहुराष्ट्रीय समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। इस समूह की बुनियादी शेयरधारिता पड़ोसी देश की विदेशी इकाई के पास है। यह तलाशी अभियान इस समूह के दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु में फैले व्यावसायिक परिसरों के साथ-साथ समूह के प्रमुख पदाधिकारियों के आवासीय परिसरों में चलाया गया।

तलाशी कार्रवाई से पता चला है कि इस समूह ने भारत से बाहर अपनी संबंधित पार्टियों से तकनीकी सेवाओं की प्राप्ति के सापेक्ष बढ़े हुए भुगतान किए हैं। कर निर्धारिती कंपनी ऐसी कथित तकनीकी सेवाओं को प्राप्त करने की वास्तविकता को सही नहीं ठहरा सकी जिसके बदले में उसने भुगतान किया है और इसके अलावा इसके विचार निर्धारण का आधार भी नहीं है। कर निर्धारिती कंपनी द्वारा ऐसी सेवाओं की प्राप्ति के लिए ऐसी सेवाओं की प्राप्ति पर पांच वर्षों की अवधि में 129 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि, निर्धारिती समूह ने हाल के वित्तीय वर्षों में अपनी संबंधित पार्टी को रॉयल्टी के लिए अपनी खाता बहियों में 350 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डेबिट की है। इस तरह के खर्च ब्रांड के उपयोग और तकनीकी जानकारी से संबंधित अप्रत्यक्ष संपत्तियों के उपयोग के लिए किए गए हैं। तलाशी के दौरान, यह समूह ऐसी सेवाएं/तकनीकी जानकारी की प्राप्ति या ऐसे दावे के लिए रॉयल्टी दर के मात्रा निर्धारण के आधार को प्रमाणित करने में विफल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सेवाओं का प्रतिपादन और ऐसा रॉयल्टी भुगतान बहुत अधिक संदिग्ध और प्रथम दृष्टया, मौजूदा आयकर कानून के अनुसार व्यावसायिक व्यय के रूप में अस्वीकार्य हो जाता है।

तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूत और दर्ज किए गए बयानों से यह भी पता चलता है कि सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं प्रदान करने में लगी समूह की संस्थाओं में से एक संबंधित पक्षों से कम नेट मार्जिन ले रही है और इसका संचालन 'लो एंड नेचर' होने का दावा कर रही है। हालांकि, जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से यह संकेत मिलता है कि यह संस्था उच्च स्तरीय प्रकृति की महत्वपूर्ण सेवाएं/संचालन प्रदान कर रही है। इस पहलू में आय में 400 करोड़ रुपये का छिपाव होने का पता चला है।

तलाशी कार्रवाई में आगे यह भी पता चला है कि समूह ने भारत में अपनी कर योग्य आय को कम करने के लिए अपनी लेखा बहियों में हेरा-फेरी की है और इसके लिए खर्च के लिए अनेक प्रावधानों का सृजन, अप्रचलन के लिए प्रावधान, वारंटी के प्रावधान, संदिग्ध ऋण/कर्ज और अग्रिम राशि आदि का सहारा लिया गया है, जिनका बहुत कम या कोई वैज्ञानिक/वित्तीय तर्क नहीं है। जांच के दौरान, समूह ऐसे दावों के लिए कोई पर्याप्त और उचित औचित्य प्रदान करने में विफल रहा है।

महाराष्ट्र में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे निकाय चुनाव

0-सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

मुंबई (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दायर अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27त्न आरक्षण की बहाली की सिफारिश की गई थी। यह देखते हुए कि अंतरिम रिपोर्ट बिना अध्ययन और शोध के तैयार की गई थी। इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य और राज्य चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट लागू नहीं करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के चुनाव में 27त्न ओबीसी कोटा देने की सिफारिश की गई थी। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चर्चा करने के लिए दोपहर कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। अंतरिम रिपोर्ट में स्थानीय निकाय चुनावों में 27त्न ओबीसी कोटा देने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अंतरिम रिपोर्ट शोध और अध्ययन के बिना तैयार की गई है। राज्य सरकार ने कोर्ट में जो डाटा पेश किया, उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने डाटा पेश किया है। आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की समर्थन किया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि यह सीमा 50 प्रतिशत के कुल कोटा सीमा के पार नहीं होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर गठित आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आयोग को फटकार लगाते हुए पूछा कि आयोग को यह कैसे पता चलता है कि यह सटीक डेटा है और प्रामाणिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट में कोई डेटा पेश नहीं किया गया है। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि यह रिपोर्ट कैसे बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के 19 जनवरी 2022 के आदेश का पालन करने को कहा है। साथ ही कहा कि चुनाव में कोई आरक्षण सीट नहीं होगी। सभी सीट को जनरल सीट के रूप में नोटिफाई करने को कहा है। आयोग की रिपोर्ट से असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का आधार आंकड़ों पर आधारित और तर्क संगत बनाने को कहा।

जस्टिस एएम खानविलकर की अगुआई वाली पीठ ने आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आयोग को मुहैया कराए गए आंकड़ों की सत्यता की पड़ताल जरूर होनी चाहिए थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सीधा लिख दिया कि अन्य पिछड़ी जातियों को स्थानीय निकायों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। ये आधी अधूरी रिपोर्ट खुद रिपोर्ट करती है कि उसमें कोई आंकड़ा नहीं है और तर्क भी नहीं। ऐसे में ये कोर्ट राज्य के चुनाव आयोग सहित किसी भी संबंधित अधिकरण को ये सिफारिशें लागू करने से मना करती है।

चेन्नई की पहली दलित और सबसे कम उम्र की महिला आर प्रिया बनेंगी मेयर

चेन्नई (आरएनएस)। सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुनेत्र कडग़म ने गुरुवार को आर प्रिया को चेन्नई निगम के लिए महापौर उम्मीदवार के तौर पर नामित किया है। हालांकि डीएमके का चेन्नई निगम में बहुमत है, ऐसे में प्रिया को औपचारिक रूप से जल्द ही महापौर के रूप में चुना जाएगा। महापौर पद के लिए नामित आर प्रिया महज 28 साल की हैं। ऐसे में प्रिया चेन्नई में मेयर का पद संभालने वाली पहली दलित और सबसे कम उम्र की महिला भी होंगी।

ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) के मेयर और अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव शुक्रवार यानी 4 मार्च को होंगे। हालाँकि, डीएमके के कुल 200 वार्डों में से 153 पार्षद हैं, ऐसे में उनका मेयर चुने जाना लाजिमी है। तारा चेरियन और कामाक्षी जयरामन के बाद प्रिया चेन्नई के इतिहास में इस पद को संभालने वाली तीसरी महिला भी हैं।

153 पार्षदों के अलावा, डीएमके के सहयोगियों के पास जीसीसी में 25 अन्य पार्षद हैं। वह द्रमुक के पूर्व विधायक चेंगई शिवम की पोती हैं, ऐसे में वो एक मजबूत राजनीतिक बैकग्राउंड वाले परिवार से हैं। उनके पिता आर राजन डीएमके के क्षेत्र सह सचिव हैं।

किसी भारतीय छात्र को बंधक बनाने को लेकर कोई खबर नहीं मिली: विदेश मंत्रालय

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत ने गुरुवार को रूस और यूक्रेन दोनों देशों के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें खारकीव में भारतीय छात्रों को बंधक बनाये जाने बात कही गई है। भारत ने कहा कि उसे किसी छात्र के बंधक बनाए जाने की स्थिति का सामना करने जैसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन प्रशासन से आग्रह किया गया है कि खारकीव एवं आसपास के क्षेत्रों से छात्रों को बाहर निकालकर देश के पश्चिमी हिस्से में ले जाने के लिये विशेष ट्रेन की व्यवस्था करें ।

भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों के एक समूह को उनकी बेलगोरोद जाने की इच्छा के विपरीत खारकीव में जबरदस्ती रोक कर रखा जा रहा है और यूक्रेन के सैनिक उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाये जाने की खबरों को लेकर मीडिया के सवालों पर अपने बयान में कहा, यूक्रेन में भारतीय दूतावास अपने नागरिकों से सतत सम्पर्क बनाये हुए है । हम इस बात का संज्ञान लेते हैं कि यूक्रेन प्रशासन के सहयोग से कल कई छात्र खारकीव से बाहर निकल सके।

उन्होंने कहा, हमें किसी भारतीय छात्र के बंधक बनाने जैसी स्थिति का सामना करने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

बागची ने कहा कि हमने यूक्रेन प्रशासन से आग्रह किया है कि खारकीव एवं आसपास के क्षेत्रों से छात्रों को बाहर निकालकर देश के पश्चिमी हिस्से में ले जाने के लिये विशेष ट्रेन की व्यवस्था करें ।

गौरतलब है कि रूस ने बुधवार को कहा था कि उसके सशस्त्र बल यूक्रेन के खारकीव शहर से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिहाज से सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। भारत में रूसी दूतावास के एक अधिकारी ने रूस के रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग का ब्योरा साझा किया था।

मॉस्को में रक्षा मंत्रालय ने एक मीडिया ब्रीफिंग में यह आरोप भी लगाया था यूक्रेन में भारतीय छात्रों के एक समूह को उनकी बेलगोरोद जाने की इच्छा के विपरीत खारकीव में जबरदस्ती रोक कर रख रहे हैं।

हालांकि भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि यूक्रेन जो अपना खून बहा रहा है, वह वहां फंसे हुए विदेशी छात्रों की मदद कर रहा है।

वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस क्षेत्र में रूस, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, माल्डोवा सहित अन्य देशों से प्रभावी ढंग से समन्वय कर रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकाल लिया गया है।

बागची ने कहा, इसे संभव बनाने के लिये यूक्रेन प्रशासन की मदद की हम सराहना करते हैं।

ऑपरेशन गंगा ' के तहत यूक्रेन से 200 छात्र और भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे

भारत सरकार के 'ऑपरेशन गंगा' के तहत यूक्रेन से लगभग 200 छात्रों और भारतीय नागरिकों को निकालकर भारत वापस लाया गया है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने स्वदेश लौटने वाले इन छात्रों और नागरिकों का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। स्वदेश लौटने वाले इन लोगों में अधिकांश छात्र थे। इंडिगो की यह विशेष उड़ान आज सुबह दिल्ली पहुंची थी। सभी स्वदेश लौटने वालों का स्वागत करते हुए, केन्द्रीय मंत्री खुबा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार यूक्रेन से सभी भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्रों को यह आश्वासन दिया कि उनके मित्रों एवं सहयोगियों को भी जल्द ही यूक्रेन से निकाल लिया जाएगा। भारत वापस लौटने पर अपने परिवारों के साथ मुलाकात करते हुए छात्रों ने केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। विमान में सवार एक युवा छात्र ने खुशी से आंसू बहाते हुए कहा कि युद्ध से संकटग्रस्त देश से सुरक्षित निकासी किसी चमत्कार से कम नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे संभव बनाया है।